COVID-19 महामारी में नियोक्ता की जिम्मेदारी से इनकार करने के लिए "फोर्स मेज्योर" का उपयोग करना!

श्रमिकों को COVID-19 महामारी में नियोक्ताओं की तरफ से काम से नहीं निकालना चाहिए और व्यवसाय को अस्थायी रूप से बंद करने पर भी मजदूरी का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। यह क्षेत्र भर में सरकार की नीति प्रतिक्रियाओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। नियोक्ताओं को भी COVID-19 प्रतिक्रियाओं को विकसित करने के लिए यूनियनों के साथ जुड़ना होगा जो सुरक्षित काम सुनिश्चित करें और एक अस्थायी बंदी के दौरान नौकरियों और मजदूरी की सुरक्षा करें। सरकारों को भी कमाई सहायता प्रदान करनी चाहिए।

एशिया-पसिफ़िक क्षेत्र के कुछ देशों में, होटल और पर्यटन उद्योग के नियोक्ता COVID -19 संकट को "कानूनी प्रक्रिया के बिना और अपने दायित्वों को पूरा किए बिना रोजगार अनुबंधों को समाप्त करने के लिए, मजबूर करने के लिए और ""अप्रत्याशित घटना"" के रूप में नामित करने की कोशिश कर रहे हैं।

फोर्स मेज्योर (जिसका अर्थ है "वरिष्ठ बल") एक सरकार, कंपनी या किसी व्यक्ति या संस्थान के नियंत्रण से परे एक घटना को दर्शाता है। इस तरह के आयोजनों में एक महत्वपूर्ण पैमाने पर युद्ध, दंगे या अपराध की लहरें शामिल हो सकती हैं, या "भगवान का कार्य" (तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, आदि) के कानूनी शब्द द्वारा वर्णित घटना। एक घटना के बल के रूप में वर्णित घटना का अर्थ है कि एक सरकार, कंपनी या कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है और दायित्व या जिम्मेदारी से मुक्त है। ज्यादातर मामलों में, कानून या अनुबंधों के खंड केवल बल की अवधि के लिए पार्टियों के दायित्वों को निलंबित करते हैं।

अधिकांश देशों में फोर्स मेज्योर की आवश्यकता के लिए कानूनी आवश्यकताएं सख्त हैं। न केवल कंपनी, व्यक्तिगत या संस्था को यह साबित करना चाहिए कि घटना उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण थी, उन्हें यह भी साबित करना होगा कि घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि स्थिति स्पष्ट रूप से उन्हें अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है और ऐसा करने में कोई बुरा विश्वास नहीं है।

कुछ नियोक्ता रोजगार अनुबंधों को समाप्त करने और नियोक्ता की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने के लिए COVID-19 महामारी के रूप में फोर्स मेज्योर करने का प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, कई कारण हैं कि क्यों फोर्स मेज्योर नहीं दिया जा सकता है और इस स्थिति में लागू नहीं किया जाना चाहिए।

SARS-Cov-2 वायरस के कारण होने वाली COVID-19 बीमारी का प्रकोप और प्रसार एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि मानवीय कार्यों (या निष्क्रियता) और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रिय स्तर पर सरकारों और संस्थानों की विफलता का परिणाम है, महामारी बनने से फैलने वाली महामारी को रोकना। इससे पता चलता है कि COVID-19 महामारी एक प्राकृतिक घटना नहीं है और "ईश्वर के कार्य" की कानूनी परिभाषा के दायरे में नहीं आती है। [यह कानून की नजर में है, धार्मिक विश्वास नहीं।]

क्षेत्र के अधिकांश सामान्य कानून और नागरिक कानून में "महामारी", "व्यापक रोग" या "प्रकोप" फोर्स मेज्योर की परिभाषा में शामिल नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रम और रोजगार कानूनों द्वारा शासित अनुबंधों में फोर्स मेज्योर के नियम शामिल नहीं हैं। COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप केवल कानूनी रूप से सिद्ध दिवालियापन को प्रभावी रूप से समाप्त होने वाले दायित्वों के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि, दिवालियापन को बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों के परिसमापन की आवश्यकता होती है - विशेषाधिकार प्राप्त लेनदारों के रूप में कर्मचारियों के लिए वित्तीय दायित्वों सहित।

फोर्स मेजर का दावा करने वाले नियोक्ताओं में से कोई भी दिवालिया या तरलता का सामना नहीं कर रहा है। होटल की संपत्ति, उदाहरण के लिए, केवल COVID-19 महामारी के दौरान अस्थायी रूप से बंद हैं और महामारी के समाप्त होने और आपातकालीन उपायों को हटा दिए जाने के बाद व्यापार फिर से शुरू हो जाएगा। यह विशेष रूप से स्वामित्व वाले और/या व्यावसायिक समूहों द्वारा संचालित होटलों के लिए महत्वपूर्ण है जो दिवालियापन का सामना नहीं कर रहे हैं। यह केवल व्यापार का एक अस्थायी निलंबन है।

कोविड-19 महामारी को स्थायी बंद करने और सामूहिक समाप्ति के औचित्य के रूप में व्यवहार करने के लिए, जबकि संकट के बाद फिर से खोलने के लिए व्यापार को बनाए रखना, बुरे विश्वास का एक कार्य है और यह बड़ीता को मजबूर करने के लिए विशेषता के अधिकार की उपेक्षा करता है। इसके अलावा, कोई भी व्यावसायिक समूह या निगम जो बल के उपयोग से श्रमिकों को समाप्त करता है, किसी भी सरकारी सहायता के लिए पात्र नहीं होना चाहिए या सरकारी प्रोत्साहन पैकेजों से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।